> रणनीति के बिना वित्तीय संसाधन संख्या मात्र है, और वित्तीय संसाधन रणनीति के बिना स्वप्न मात्र है.
>
> —इमैनुएल फेबर[1]

9

वित्तीय प्रबंधन

31 मार्च 2021 को हमारा तुलन पत्र ₹6.6 लाख करोड़ पर बंद हुआ. महामारी से ग्रस्त वर्ष में 23.6% की विकास दर के साथ वित्तपोषण करना चुनौतीपूर्ण रहा. हमने व्यावसायिक परिचालनों का वित्तपोषण करने के लिए विभिन्न अवसरों का उपयोग करने के साथ-साथ उधारीकरण लागत को कम से कम रखने के भी प्रयास किए. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान की गई विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) और अतिरिक्त विशेष चलनिधि सुविधा (एएसएलएफ) ने ऋणयोग्य निधियों को बढ़ाने में नाबार्ड की सहायता की है. निवेश का निधीयन करने का नाबार्ड का अग्रसक्रिय दृष्टिकोण महामारी वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हुआ.

9.1 निधियों के स्रोत

वर्ष के दौरान हमारे अधिकांश संसाधनों का निर्माण जमाराशियों, बॉण्डों और मुद्रा बाज़ारों से उधार तथा नाबार्ड की स्वाधिकृत निधियों से हुआ. वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में ₹1,25,723 करोड़ की वृद्धिशील निधियों में, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी), बॉण्डों बैंकों से मीयादी ऋणों और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विशेष चलनिधि सुविधा में से प्रत्येक का योगदान ₹20,000 करोड़ से भी अधिक था. वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021 में एक ओर जहां जमाराशियों और स्वाधिकृत निधियों का हिस्सा कम हुआ वहीं बॉण्डों, डिबेंचरों और उधारियों का हिस्सा बढ़ गया. कुल संसाधनों का पाँचवाँ हिस्सा केवल ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की जमाराशियों का रहा, जो सर्वाधिक था (चित्र 9.1 और परिशिष्ट तालिका अ9.1).

9.1.1 स्वाधिकृत निधियां

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की चुकता पूंजी ₹15,080 करोड़ रही जिसमें वर्ष के दौरान भारत सरकार का ₹1000 करोड़ का योगदान शामिल है. ₹30,000 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी ने पूंजी निवेश के लिए आवश्यक क्षमता उपलब्ध कराई. पूंजी, प्रारक्षित निधियां, अधिशेष और स्वाधिकृत निधियां वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में 8.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बढ़कर ₹70,443 करोड़ (तुलनपत्र का 10.7%) तक पहुंच गईं. इस अवधि के दौरान प्रारक्षित निधियां और अधिशेष 12.4% बढ़कर ₹39,269 करोड़ हो गए.

चित्र 9.1: निधियों के स्रोत

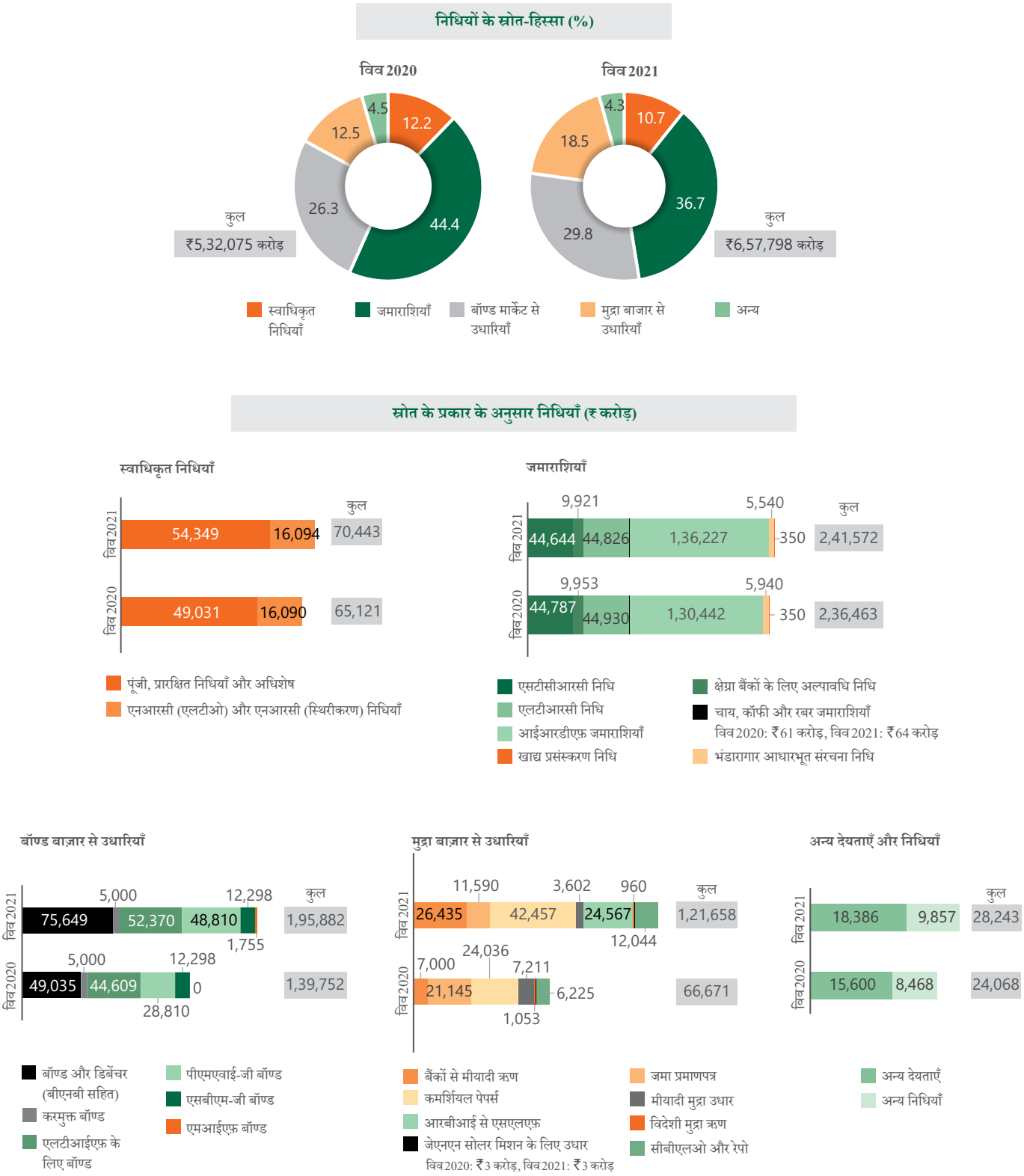

नोट: बीएनबी = भविष्य निर्माण बॉण्ड; सीबीएलओ = संपार्श्विक उधार एवं ऋण वितरण दायित्व; जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन; एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि; एलटीआरसी = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण; एमआईएफ = सूक्ष्म-सिंचाई निधि; एनआरसी (एलटीओ) = राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन); एनआरसी (स्टेबिलाइजेशन) = राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण); पीएमएवाई-जी = प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण; आरबीआई = भारतीय रिज़र्व बैंक; आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि; क्षेत्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; एसबीएम-जी = स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण; एसएलएफ = विशेष चलनिधि निधि; एसटी = अल्पावधि; एसटीसीआरसी = अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण.

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निवेश ऋणों के पुनर्वित्त के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) [एनआरसी(एलटीओ)] निधि के अंतर्गत ₹14,497 करोड़ की राशि और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अल्पावधि ऋणों के परिवर्तन/पुन:अनुसूचीकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) [एनआरसी (स्टेबिलाइजेशन)] निधि के अंतर्गत ₹1,597 करोड़ की राशि लेखा बहियों में शेष रही. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रत्येक ने इन दोनों निधियों में ₹1 करोड़ का अंशदान किया.

9.1.2 जमाराशियां

नाबार्ड को विभिन्न प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अपनी विभिन्न निधियों के संवर्धन के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधारीकरण में हुई कमी की राशि का उपयोग करने की अनुमति दी जाती रही है. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ऐसी निधियों के अंतर्गत बकाया राशि बढ़कर ₹2,41,572 करोड़ हो गई जो कुल आस्तियों का 36.7% हिस्सा थी. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) निधि के तहत ₹44,644 करोड़ की राशि, अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (एसटीआरआरबी) जमाराशियों के तहत ₹9,921 करोड़ की राशि, और दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) के तहत ₹44,826 करोड़ की राशि बकाया थी. भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि की खेप - XXVI के लिए ₹30,000 करोड़ की राशि आबंटित की है. नाबार्ड ने वर्ष के दौरान ₹27,539 करोड़ की राशि जुटाई और वर्ष के दौरान आरआईडीएफ़ जमाराशियों के अंतर्गत ₹21,754 करोड़ की राशि की चुकौती कर दी. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया आरआईडीएफ जमाराशियां बढ़कर ₹1,36,227 करोड़ हो गईं.

वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में भंडारागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) के लिए ₹5,540 करोड़ और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) के लिए ₹350 करोड़ की जमाराशि बकाया रही. वर्ष के दौरान भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ₹800 करोड़ के आहरण हुए और ₹1,200 करोड़ की चुकौती हुई जबकि खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत आहरण और चुकौती, प्रत्येक ₹50 करोड़ की रही.

9.1.3 उधार

नाबार्ड, ऋण की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बॉण्डों और मुद्रा बाज़ारों के साथ-साथ अन्य माध्यमों से अपने संसाधनों में वृद्धि करता रहा है. समय के साथ नाबार्ड ने अपने संसाधनों की पाइपलाइन में कॉरपोरेट बॉण्डों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों, मीयादी मुद्रा उधारों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से मीयादों ऋणों, भारतीय रिज़र्व बैंक से विशेष चलनिधि सुविधा इत्यादि को भी शामिल कर लिया है.

बॉण्ड बाज़ार से उधार

1. **बॉण्ड और डिबेंचर्स:** 31 मार्च 2021 की स्थिति में, नाबार्ड के पूंजी अभिलाभ बॉण्ड गत वर्ष के समान ही ₹1.3 करोड़ के रहे. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ₹11,835 करोड़ के कॉरपोरेट बॉण्डों का मोचन किया गया, जबकि ₹38,855 करोड़ के नए बॉण्ड जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप इसके अंतर्गत बकाया राशि ₹75,649 करोड़ हो गई. 31 मार्च 2020 की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति में यह बकाया 1.56 गुना बढ़ गया.
2. **भारत सरकार की योजनाओं के लिए बॉण्डों के माध्यम से जुटाई गई निधियां:**
   क. दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के अंतर्गत नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान भारत सरकार द्वारा सर्विस्ड बॉण्डों (बजटीय संसाधनों से इतर) के रूप में ₹4,156 करोड़ और नाबार्ड सर्विस्ड बॉण्डों के रूप में ₹3,605 करोड़ की राशि उधार ली. इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया एलटीआईएफ उधार बढ़कर ₹52,370 करोड़ हो गया (नाबार्ड सर्विस्ड 64.2% और भारत सरकार सर्विस्ड 35.8%).
   ख. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के बॉण्ड के अंतर्गत बकाया राशि ₹48,810 करोड़ तक पहुंच गई. इस प्रकार नाबार्ड ने बेघरों और पुराने जीर्णशीर्ण घरों में रहने वालों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूर्ण सर्विस्ड बॉण्डों के माध्यम से ₹20,000 करोड़ की राशि उधार ली गई.
   ग. 31 मार्च 2021 की स्थिति में, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के लिए नाबार्ड की बकाया उधारियां ₹12,298 करोड़ रहीं.
   घ. ₹5,000 करोड़ की समूह निधि के साथ वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान नाबार्ड में सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) की स्थापना की गई थी जो वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान भी जारी रही. इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के निधीयन के माध्यम से सूक्ष्म-सिंचाई का विस्तार करना और इसको अपनाने के लिए प्रधान मंत्री किसान सिंचाई योजना "प्रति बूँद-अधिक फसल (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी)" के प्रावधानों को और आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना था. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड-सर्विस्ड बॉण्डों के रूप में ₹1,755 करोड़ की राशि जुटाई गई और 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार यह पूरी राशि बकाया थी.

मुद्रा बाज़ार से उधार

वाणिज्यिक पत्रों, बैंकों से मीयादी ऋणों और भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष चलनिधि सुविधा से संसाधन संग्रहण में बड़ा उछाल आया जोकि कुल आस्तियों का 14.2% था. नाबार्ड ने वर्ष के दौरान वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से ₹92,137 करोड़ उधार लिए. ₹74,775 करोड़ के मोचन के पश्चात् 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इनके अंतर्गत ₹42,457 करोड़ की राशि बकाया रह गई जबकि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹24,036 करोड़ थी. वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों से मीयादी ऋणों के रूप में ₹34,000 करोड़ उधार लिए गए जिसमें 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹26,435 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020 में यह राशि ₹7,000 करोड़ थी) की राशि बकाया थी. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ₹11,590 करोड़ मूल्य के जमा प्रमाणपत्र संग्रहीत किए गए और ₹22,550 करोड़ के जमा प्रमाणपत्रों का मोचन किया गया. इस प्रकार 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इसके अंतर्गत ₹12,075 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि बकाया रही. त्रिपक्षीय रेपो और रेपो उधार (बकाया राशि ₹12,044 करोड़); सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से मीयादी मुद्रा उधार (बकाया राशि ₹3,602 करोड़); वित्तीय वर्ष 2021 के

दौरान कोई नया बॉण्ड जारी किए बगैर 2016 में संग्रहीत कर-मुक्त बॉण्ड (बकाया राशि ₹5,000 करोड़); और विदेशी मुद्रा उधार (एफसीबी) (बकाया राशि ₹960 करोड़)[1] जैसे कुछ अन्य माध्यमों से संसाधन जुटाए गए.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में घोषित ₹25,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा और ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त विशेष चलनिधि सुविधा से ग्रामीण ऋण वितरण को बल मिला. विशेष चलनिधि सुविधा का उद्देश्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं (एमएफआई) की नकदी की कमी को दूर करना था, जबकि अतिरिक्त विशेष चलनिधि सुविधा का उद्देश्य छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करना था. विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹23,000 करोड़ (वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक से ली गई ₹25,000 करोड़ की राशि के समक्ष) की राशि बकाया थी. वर्ष के दौरान अतिरिक्त विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत आहरित ₹1,567 करोड़ की पूरी राशि बकाया थी.

9.2 निधियों के उपयोग

समीक्षाधीन वर्ष में कोविड-19 महामारी के कारण ग्रामीण वित्तीय एजेंसियों और हमारे ग्राहकों को अनेक प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ा. कारोबार ठप्प हो जाने के कारण उनके ग्राहकों से ऋणों की चुकौती में चूक हुई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणों की वसूली अधिस्थगित कर दी. इससे हमारे ग्राहकों की वित्तीय स्थिति भी कमजोर हो गई, जिससे वे नाबार्ड जैसी एजेंसियों से निधियाँ प्राप्त करने हेतु अपात्र हो गए और वे उच्चतर लागत वाले उधार लेने के लिए बाध्य हो गए. भारत सरकार के पैकेजों, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग और स्थिति को संभालने की नाबार्ड की अपनी पहल की बदौलत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से हम विकासात्मक कार्यों के लिए नाबार्ड की ओर से निधि उपलब्ध करा सके. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान नाबार्ड ने ग्रामीण उत्पादन और निवेश के लिए आधारस्तरीय ऋण (जीएलसी) में वृद्धि करने के अपने विकास एजेंडा हेतु आधारभूत संरचना सृजन, सामाजिक क्षेत्र के विकास, नकदी और निवेश प्रबंधन और अचल आस्तियों के सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निधि जुटायी. (चित्र 9.2 और परिशिष्ट तालिका अ9.2).

9.2.1 पुनर्वित्त के माध्यम से आधार स्तरीय ऋण में वृद्धि

नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम प्रदान करता है और वे मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) और कृषि में निवेश के लिए किसानों का वित्तपोषण करते हैं. हमारा पुनर्वित्त कई अन्य प्रयोजनों जैसे बुनकरों और कारीगरों को कार्यशील पूंजी ऋण; विपणन सहायता; प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अल्पावधि ऋणों के मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन के लिए भी दिया जाता है. नाबार्ड ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को प्रत्यक्ष ऋण भी प्रदान करता है. नाबार्ड के तुलनपत्र का आधा भाग ऐसे सभी प्रकार के ऋणों से बनता है जो आधार स्तरीय ऋण में सुधार लाने, विपणन के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के संसाधनों में वृद्धि अधिप्राप्ति के लिए संसाधनों को बढ़ाने, आदि में सहायता करते हैं.

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड द्वारा दिए गए विभिन्न ऋणों और अग्रिमों के समक्ष निधियों के अभिनियोजन और वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

1. नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए कुल ऋण और अग्रिम ₹6 लाख करोड़ तक पहुंच गए जबकि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ये ₹4.8 लाख करोड़ थे. महामारी के बावजूद इनमें 25.2% की प्रभावशाली वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह वृद्धि 11.5% थी.
2. आधार स्तर पर ऋण वितरण के लिए उपलब्ध संसाधनों में 47.6% की वृद्धि हुई जिससे मौसमी कृषि परिचालनों (एसटी-एसएओ) और मौसमी कृषि परिचालनों से इतर [एसटी (ओएसएओ)](उत्पादन और विपणन ऋण) के लिए अल्पावधि ऋण का बकाया बढ़कर ₹1,06,372 करोड़ तक पहुंच गया जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में यह ₹68,693 करोड़ था. गत वर्ष इसमें मात्र 2.9% की ही वृद्धि हुई थी.
3. राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पावधि-मौसमी कृषि परिचालनों के ऋण क्रमश: ₹69,504 करोड़ (74.8%) और ₹23,343 करोड़ (25.2%) रहे.
4. ₹13,477 करोड़ के अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालन से इतर ऋण राज्य सहकारी बैंकों (76.2%), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (23.7%) और लघु वित्त बैंकों (0.1%) के बीच वितरित किए गए.
5. विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत ₹18,763 करोड़ की राशि बकाया थी जिसमें राज्य सहकारी बैंकों का हिस्सा 67.7% था और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (32.3%) का स्थान आता है.
6. आधार स्तर पर पूंजी निर्माण को बल मिला, क्योंकि बैंकों द्वारा प्रदान किए गए मध्यावधि और दीर्घावधि निवेश ऋणों के समक्ष बकाया पुनर्वित्त 19.4% की वृद्धि के साथ ₹1,99,510 करोड़ तक पहुंच गया जबकि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार यह ₹1,67,098 करोड़ था. गत वर्ष मध्यावधि (एमटी) और दीर्घावधि (एलटी) पुनर्वित्त में 10.2% की वृद्धि हुई थी.
7. प्रत्यक्ष ऋण वितरण विंडो के अंतर्गत ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए गए ऋणों में 50% की वृद्धि हुई, यद्यपि कुल आस्तियों में इसका हिस्सा सबसे कम था.
8. कुल आस्तियों में मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋणों का हिस्सा सबसे अधिक 30.3% था. उत्पादन और विपणन ऋणों का हिस्सा लगभग 16.2% दर्ज हुआ. हमारे पोर्टफोलियों में इन दो मदों ने कुल आस्तियों की तुलना में उच्च वृद्धि और उच्च हिस्सा दर्ज किया.
9. कुल आस्तियों में 3% की निम्न हिस्सेदारी के साथ संघों हेतु ऋण सुविधाएं 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 65.3% की अत्यंत उच्च वृद्धि दर्ज करते हुए ₹20,038 करोड़ हो गईं.

9.2.2 आधारभूत संरचना के लिए वित्तपोषण

1. हमारी आस्तियों का लगभग एक तिहाई हिस्सा आधारभूत संरचनाओं के वित्तपोषण के कारण है.
2. हमारी आस्तियों का पाँचवा हिस्सा आरआईडीएफ के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं के बकाया ऋणों का है. ये ऋण 31 मार्च 2020 की तुलना में 5.6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹1,32,724 करोड़ हो गए.
3. 31 मार्च 2021 की स्थिति में नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के तहत ऋण ₹17,999 करोड़ रहे और दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के तहत ऋण ₹51,713 करोड़ रहे.

चित्र 9.2: निधियों के उपयोग

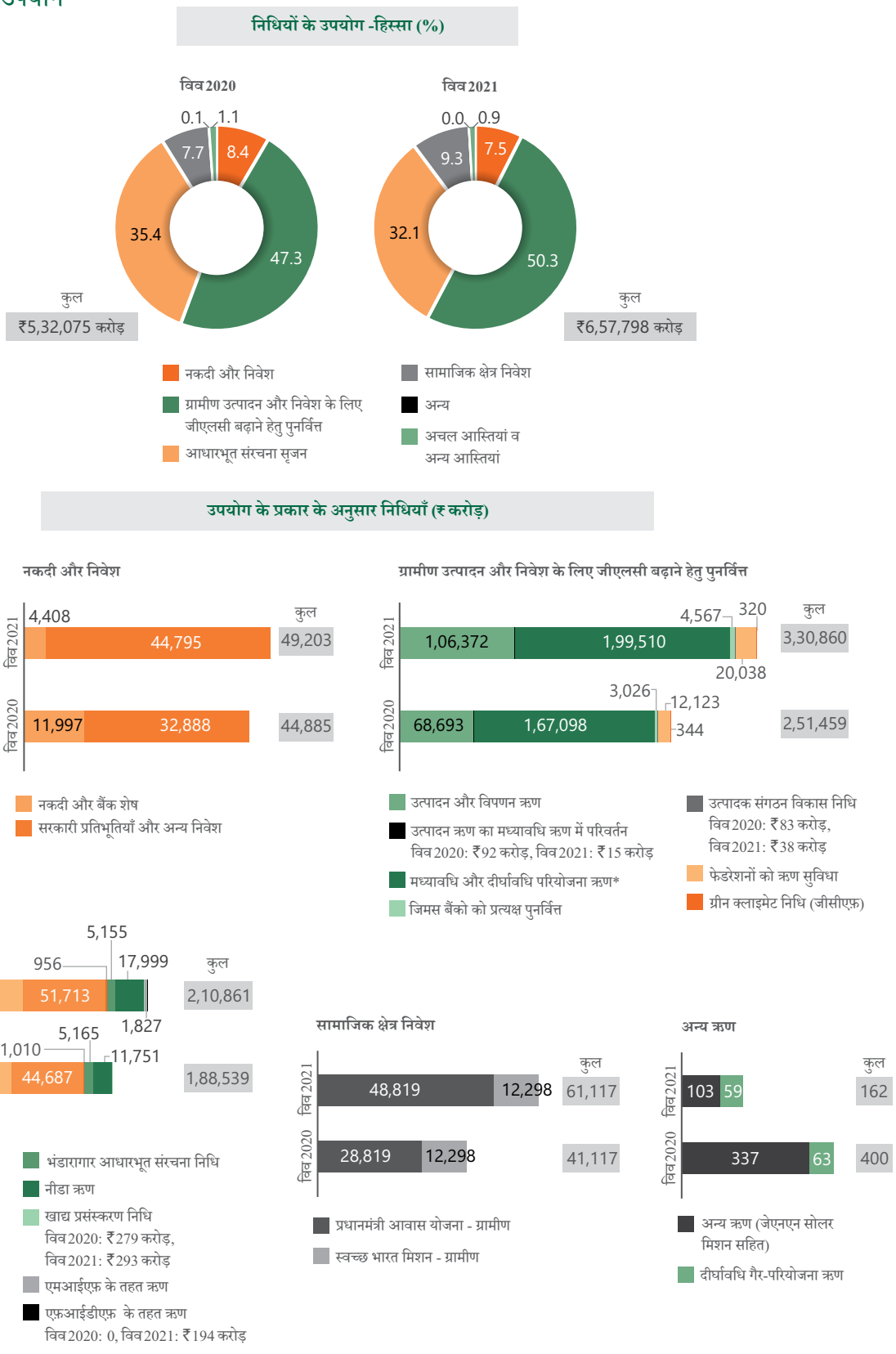

* मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋणों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर शामिल हैं.

नोट: डीसीसीबी = ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; एफआईडीएफ = मत्स्यपालन आधारभूत संरचना विकास निधि; जीएलसी = आधारस्तरीय ऋण; जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन; एलटी = दीर्घावधि; एमआईएफ = सूक्ष्म-सिंचाई निधि; एमटी = मध्यावधि; एनआईडीए = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता; आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि; एसटी = अल्पावधि.

9.2.3 सामाजिक क्षेत्र निवेश

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते आवास उपलब्ध कराने में सक्रिय सहभागिता दर्शाते हुए, हमारे पोर्टफोलियो में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ₹48,819 करोड़ के ऋण बकाया हैं. ये ऋण राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी को प्रदान किए गए थे. इन ऋणों में 69.4% की वृद्धि दर्ज हुई और कुल आस्तियों में इनका हिस्सा 7.4% रहा.
2. नाबार्ड ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की है.

9.2.4 अधिशेष निधियों का निवेश

नाबार्ड द्वारा विभिन्न वित्तीय लिखतों और बैंकों में जमाराशियों के रूप अभिनियोजित अल्पावधि अधिशेष की प्रमात्रा 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹47,740 करोड़ रही जो तुलनपत्र का 7.3% हिस्सा है. इसमें से 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 94% प्रतिशत हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय लिखतों में अभिनियोजित किया गया, ₹2,945 करोड़ की राशि को चलनिधि एवं आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए अल्पावधि बैंक जमाराशि के रूप में रखा गया.

9.3 आय और व्यय

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ₹34,671.2 करोड़ की आय अर्जित की है अर्थात् इसमें वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में 6.1% की वृद्धि हुई है (चित्र 9.3-9.7). वित्तीय वर्ष 2021 का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹6,081.4 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020 के ₹5,234.3 करोड़ के समक्ष) रहा और कर-

चित्र 9.3: सकल आय (₹ करोड़)

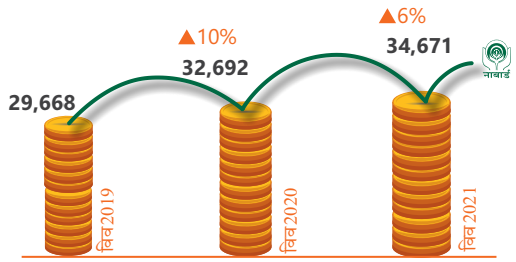

चित्र 9.4: कर पश्चात लाभ (₹ करोड़)

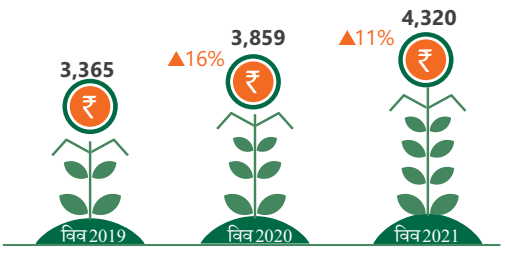

चित्र 9.5: जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (%)

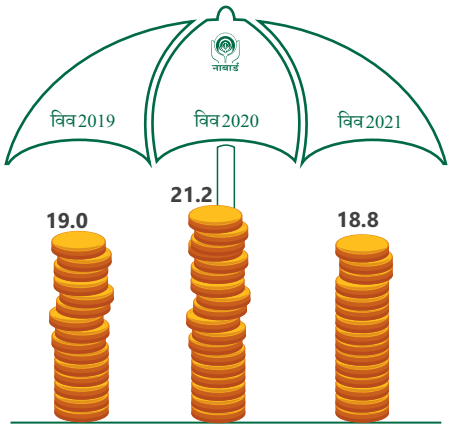

चित्र 9.6: प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़)

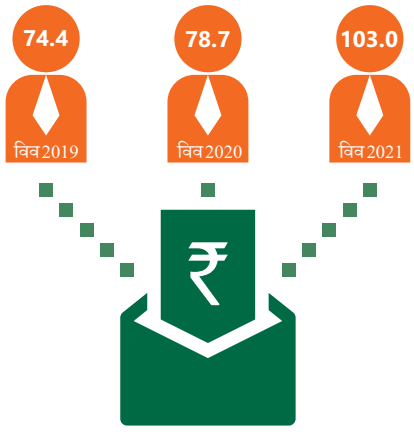

चित्र 9.7: प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)

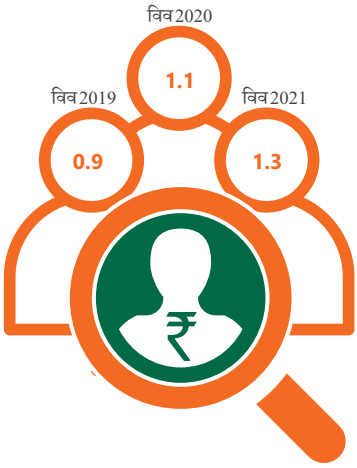

पश्चात् लाभ (पीएटी) ₹4,320 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020 के ₹3,859.2 करोड़ के समक्ष) रहा. निवल अधिशेष को अनुसंधान और विकास निधि, प्रारक्षित निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि एवं अन्य निधियों सहित नाबार्ड में स्थापित विभिन्न निधियों में अंतरित कर विनियोजित किया गया.

चित्र 9.8: नाबार्ड की सहायक संस्थाओं में शेयरधारिता

9.4 अन्य कंपनियों में नाबार्ड का हिस्सा

9.4.1 नाबार्ड की सहायक संस्थाओं में निवेश

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021 में नैबसंरक्षण को अपनी चौथी-पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में पंजीकृत करवाया (इस प्रकार नाबार्ड की कुल सहायक संस्थाओं की संख्या सात हो गई) (चित्र 9.8). हमें वित्तीय वर्ष 2020 के लिए लाभांश के रूप में नैबकॉन्स से ₹10 लाख प्राप्त हुए.

9.4.2 रणनीतिक निवेश

31 मार्च 2021 तक हमने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत नौ निकायों में ₹1,066.2 करोड़ की राशि का निवेश किया था. ₹966.3 करोड़ के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का सबसे बड़ा हिस्सा था जबकि ₹40,000 के साथ भारतीय कृषि कौशल परिषद का हिस्सा सबसे छोटा था.

9.4.3 वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों और प्रौद्योगिकी का प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से हमने 21 वैकल्पिक निवेश निधियों अथवा एआईएफ (जिसे पहले जोखिम पूंजी निधि कहा जाता था) में ₹528 करोड़ (₹338 करोड़ संवितरित) का निवेश किया है. इसने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की 67 पोर्टफोलियो कंपनियों में ₹1470.4 करोड़ के निवेश को उत्प्रेरित किया. इनमें कृषि-बीमा के कारोबार के क्षेत्र में ग्राम कवर; एरगॉस बिज़नेस सोल्यूशन्स प्रा. लि. - एक अनाज बैंक; क्लोनेक ऑटोमेशन सिस्टम्स प्रा.लि. - एक अर्ध-स्वचालित मृदा परीक्षण समाधान (इसका वाणिज्यिक नाम है, कृषितंत्र) के नाम शामिल हैं (तालिका 9.1).

तालिका 9.1: जोखिम पूंजी निधियों में निवेश (₹ करोड़)

निधि का नाम	*प्रतिबद्धता*	*संवितरित*	*बकाया*
आविष्कार भारत फंड	25.0	19.9	17.6
अंकुर कैपिटल फंड II	10.0	1.8	1.8
एपीआईडीसी - जैव प्रौद्योगिकी उद्यम निधि	5.0	5.0	4.8
एपीआईडीसी - वेंचरिस्ट लाइफ फंड – III	17.4	18.6	10.6
गोल्डन गुजरात ग्रोथ फंड I	10.0	10.0	8.0
जीवीएफएल स्टार्टअप फंड	10.0	6.3	6.3
आईएफएमआरएफ इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म क्रेडिट फंड	10.0	10.0	10.0

निधि का नाम	*प्रतिबद्धता*	*संवितरित*	*बकाया*
इंडिया एडवांटेज फंड एस4I	10.0	7.4	5.1
इंडिया ऑपरच्यूनिटीज फंड	20.0	18.4	12.1
इंडिया निवेश ग्रोथ एण्ड स्पेशल सिचुएशन फंड	5.0	5.0	5.0
इवीकैप वेंचर्स ट्रस्ट फंड I	20.0	20.0	16.1
इवीकैप वेंचर्स ट्रस्ट फंड II	10.0	10.0	10.0
जेएम फाइनैंशियल इंडिया फंड II	10.0	7.1	6.2
नैबवेंचर्स फंड – I	200.0	53.9	53.9
ओम्नीवोर कैपिटल 1 इंडिया	25.0	24.2	23.7
ओरियोस वेंचर पार्ट्नर्स फंड II	10.0	10.0	10.0
एसईएएफ इंडिया एग्रिबिज़नेस फंड	10.6	10.0	8.9
स्टेकबोट कैपिटल फंड I	10.0	7.0	5.5
टाटा कैपिटल इन्नोवेशन्स फंड	60.0	59.7	59.7
टीवीएस श्रीराम ग्रोथ फंड 3	25.0	8.9	8.9
टीवीएस श्रीराम ग्रोथ फंड 1बी	25.0	25.0	0.0
कुल	**528.0**	**338.2**	**284.0**

नोट: नैबवेंचर्स फंड-I, नैबवेंचर्स लि. द्वारा प्रबंधित एक निधि है. नैबवेंचर्स लि. नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था है.

दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार वैकल्पिक निवेश निधियों में ₹284 करोड़ का निवेश रहा. वित्त वर्ष 2021 के दौरान:

- आविष्कार भारत फंड ने कोट्टारम एग्रो फूड्स (सोलफुल) के अपने शेयर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लि. को बेचे.
- आई इविकैप वेंचर्स ट्रस्ट फंड I ने सेकेंडरी डील के माध्यम से मानश लाइफस्टाइल (पर्पल) के शेयर बेचे.
- टीवीएस श्रीराम ग्रोथ फंड 1बी ने एनएसई और प्रभात डेयरी के अपने शेयर कई बार में बेचे; और
- एपीआईडीसी-वेंचरिस्ट लाइफ फंड-III ने रिचकोर लाइफ साइंसेज़ के शेयर लॉरल लैब्स को बेचे.

नोट

1. डैनोने के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. केएफडब्ल्यू से लिये गए उधारों के तहत वर्ष के दौरान ₹59 करोड़ का मोचन किया गया. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार के तहत ₹1,053 करोड़ की राशि बकाया थी. नाबार्ड की डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार विनिमय दर के समक्ष विदेशी मुद्रा बॉण्डों को स्वैप करारों के माध्यम से हेज किया जाता है.

अध्याय 9 का परिशिष्ट

तालिका अ9.1: निधियों के स्रोत

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	
	राशि (₹ करोड़)	हिस्सा (%)	राशि (₹ करोड़)	हिस्सा (%)
स्वाधिकृत निधियां	**65,121**	**12.2**	**70,443**	**10.7**
पूंजी, प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	49,031	9.2	54,349	8.3
एनआरसी (एलटीओ) और एनआरसी (स्थिरीकरण) निधियां	16,090	3.0	16,094	2.4
जमाराशियां	**2,36,463**	**44.4**	**2,41,572**	**36.7**
एसटीसीआरसी निधि	44,787	8.4	44,644	6.8
क्षेग्रा बैंको हेतु अल्पावधि निधि	9,953	1.9	9,921	1.5
एलटीआरसी निधि	44,930	8.4	44,826	6.8
चाय, काफी और रबर जमाराशियां	61	0.0	64	0.0
आरआईडीएफ जमाराशियां	1,30,442	24.5	1,36,227	20.7
भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	5,940	1.1	5,540	0.8
खाद्य प्रसंस्करण निधि	350	0.1	350	0.1
बॉण्ड बाज़ार में उधार	**1,39,752**	**26.3**	**1,95,883**	**29.8**
बॉण्ड और डिबेंचर (बीएनबी सहित)	49,035	9.2	75,650	11.5
कर मुक्त बॉण्ड	5,000	0.9	5,000	0.8
एलटीआईएफ के लिए बॉण्ड	44,609	8.4	52,370	8.0
पीएमएवाई-जी के लिए बॉण्ड	28,810	5.4	48,810	7.4
एसबीएम-जी के लिए बॉण्ड	12,298	2.3	12,298	1.9
एमआईएफ के लिए बॉण्ड	0	0.0	1,755	0.3
मुद्रा बाजार से उधार	**66,673**	**12.5**	**1,21,658**	**18.5**
बैंकों से मीयादी ऋण	7,000	1.3	26,435	4.0
जमा प्रमाणपत्र	21,145	4.0	11,590	1.8
कमर्शियल पेपर्स	24,036	4.5	42,457	6.5
मीयादी मुद्रा उधार	7,211	1.4	3,602	0.6
भारतीय रिज़र्व बैंक से एसएलएफ	0	0.0	24,567	3.7
विदेशी मुद्रा ऋण	1,053	0.2	960	0.1
जेएनएन सोलर मिशन के लिए उधार	3	0.0	3	0.0
सीबीएलओ और रेपो	6,225	1.2	12,044	1.8
अन्य	**24,066**	**4.5**	**28,242**	**4.3**
अन्य देयताएं	15,600	2.9	18,386	2.8
अन्य निधियां	8,466	1.6	9,856	1.5
कुल	**5,32,075**	**100.0**	**6,57,798**	**100.0**

नोट: बीएनबी = भविष्य निर्माण बॉण्ड; सीबीएलओ = संपार्श्विक उधार और ऋण वितरण दायित्व; जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन; एलटीआईएफ = दीर्घावधि सिंचाई निधि; एलटीआरसी = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण; एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि; एनआरसी (एलटीओ) = राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन); एनआरसी (स्थिरीकरण) = राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण); पीएमएवाई-जी = प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण; आरबीआई = भारतीय रिज़र्व बैंक; आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि; क्षेग्राबैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; एसएमबी-जी = स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण; एसएलएफ = विशेष चलनिधि निधि; एसटी = अल्पावधि; एसटीसीआरसी = अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण.

तालिका अ9.2: निधियों के उपयोग

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	
	राशि (₹ करोड़)	हिस्सा (%)	राशि (₹ करोड़)	हिस्सा (%)
नकदी और निवेश	**44,885**	**8.4**	**49,203**	**7.5**
नकदी और बैंक शेष	11,997	2.3	4,408	0.7
सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य निवेश	32,888	6.2	44,795	6.8
सीबीएलओ / त्रि-पक्षीय रेपो ऋण	0	0.0	0	0.0
ग्रामीण उत्पादन और निवेश के लिए जीएलसी बढ़ाने हेतु पुनर्वित्त	**2,51,459**	**47.3**	**3,30,860**	**50.3**
उत्पादन और विपणन ऋण	68,693	12.9	1,06,372	16.2
उत्पादन ऋण का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन	92	0.0	15	0.0
मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण*	1,67,098	31.4	1,99,510	30.3
जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	3,026	0.6	4,567	0.7
उत्पादक संगठन विकास निधि	83	0.0	38	0.0
फेडरेशनों को ऋण सुविधा	12,123	2.3	20,038	3.1
ग्रीन क्लाइमेट फंड	344	0.1	320	0.1
आधारभूत संरचना सृजन (ऋण से)	**1,88,539**	**35.4**	**2,10,861**	**32.1**
आरआईडीएफ	1,25,647	23.6	1,32,724	20.2
दीर्घावधि सिंचाई निधि	44,687	8.4	51,713	7.9
डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि	1,010	0.2	956	0.2
भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	5,165	1.0	5,155	0.8
नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता	11,751	2.2	17,999	2.7
खाद्य प्रसंस्करण निधि	279	0.1	293	0.0
सूक्ष्म सिंचाई निधि	0	0.0	1,827	0.3
मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि	0	0.0	194	0.0
सामाजिक क्षेत्र निवेश	**41,117**	**7.7**	**61,117**	**9.3**
प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण	28,819	5.4	48,819	7.4
स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण	12,298	2.3	12,298	1.9
अन्य	**400**	**0.1**	**162**	**0.0**
अन्य ऋण (जेएनएन सोलर मिशन सहित)	337	0.1	103	0.0
दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	63	0.0	59	0.0
ऋण और अग्रिम, नकदी और निवेश का उप जोड़	**5,26,400**	**98.9**	**6,52,203**	**99.1**
अचल आस्तियां व अन्य आस्तियां	5,675	**1.1**	5,595	**0.9**
कुल	**5,32,075**	**100.0**	**6,57,798**	**100.0**

नोट:

1. मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋणों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विशेष विकास डिबेंचर शामिल हैं.
2. सीबीएलओ = संपार्श्विक उधार और ऋण वितरण दायित्व; जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; एफआईडीएफ = मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि; जीएलसी = आधार स्तरीय ऋण ; जेएनएन सोलर मिशन = जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन; एलटी = दीर्घावधि ; एमआईएफ = सूक्ष्म सिंचाई निधि; एमटी = मध्यावधि ; नीडा = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता; आरआईडीएफ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि; एसटी = अल्पावधि